सम्पूर्ण व्यापारिक दैनिक
नफा नुकसान
सोमवार, 28 जुलाई 2014

हाड़ौती विशेष

कोटा फिर बन सकता है पॉवरहाउस

भविष्य में कोटा संभाग को और अधिक सम्पन्न बनाने के लिए सरकार और कारोबारियों को मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का विस्तार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार, परिवहन, रोजगार के संसाधन सभी को मुहैया कराना इत्यादि प्रमुख हैं। इन प्रयासों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नए औद्योगिक केंद्रों की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। कोटा लघु उद्योग काउंसिल के अध्यक्ष एल.सी.बाहेती के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अच्छी उपलब्धता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर्स, एसईजेड एवं नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग संभाग स्थापना के लिए विशेष पैकेज जारी करने की मांग की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीणों के पलायन पर अंकुश लगेगा और शहरों पर दबाव कम होगा। कोटा में आबादी बढ़ने से किफायती आवासों की मांग निरंतर बढ़ रही है। सरकार शहर से बाहर बेहतर परिवहन के द्वारा किफायती आवास का निर्माण कर सकती है।

नयी जगहों पर नया विस्तार

कोटा शहर से बाहर नये बस अड्डे, एयरपोर्ट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट हब, आवासीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें इत्यादि स्थापित की जा सकती हैं। क्योंकि बेहतर इंटरनेट सेवाओं के कारण किसी भी स्थान पर स्थापित होना और कारोबार करना बेहद आसान हो गया है। ऐसे नये क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संतुलन भी किया जा सकता है।

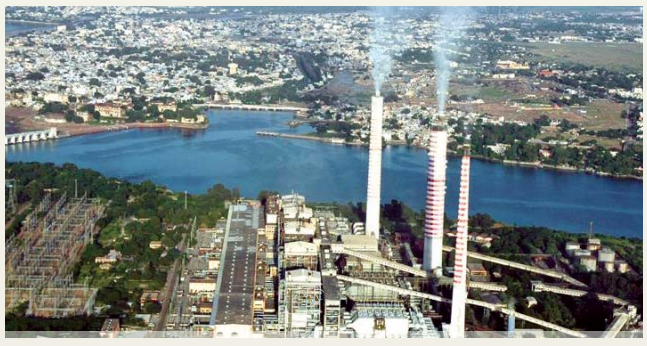

शहरीकरण का विस्तार

शहरीकरण के तहत शहरों के विस्तार तथा नये शहरों की स्थापना की आवश्यकता है। भूमि उपलब्धता में मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम बाधक बन रहा है। संभाग के बंजर, पथरीले एवं वनस्पति रहित क्षेत्रों को औद्योगिक गतिविधियों के तहत इस्तेमाल करने की नीति बननी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता काफी कम हो गई है और ढांचागत सुविधाएं संकुचित होती जा रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आगामी 20 से 25 वर्षों के लिए कोटा संभाग स्तर पर स्पष्ट योजना बननी चाहिए। इसी प्रकार शहरों में विद्युत लाईनें, पानी की पाईप लाईनें और टेलिफोन केबल्स पूर्णतया भूमिगत होनी चाहिए तथा उन्हें चिह्नित करने हेतु सतह पर 5 से 10 मीटर की दूरी पर विभाग का लोगो लगे ताकि सड़क मरम्मत या विस्तार के समय क्षतिग्रस्त होने से ये सेवायें बाधित ना हों।

हैंगिंग ब्रिज के अभाव में यातायात की समस्या

कोटा में करीब 5 वर्ष पहले एक प्रमुख पुल टूट गया था। एक देशी कंपनी और विदेशी कंपनी मिलकर इस पुल को बना रही थी। विवाद के कारण कोटा में हैंगिंग ब्रिज नहीं बन पाया है। इस कारण भारी वाहनों का यातायात कोटा शहर के बीच से गुजरता है। एसएसआई अध्यक्ष सुरेश बंसल के अनुसार सरकार को पहल करके हैंगिंग ब्रिज निर्माण को शीघ्र शुरू करवाना चाहिए जिससे कोटा शहर में यातायात संबंधी समस्या कम हो सके और दुर्घटनाओं में कमी आये।

नये एयरपोर्ट की आवश्यकता

कोटा में हल्के विमानों की उड़ान के लिए एयरपोर्ट है लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पूरे देशभर में प्रसिद्ध कोटा में बड़े विमानों के लिए एयरपोर्ट नहीं है। प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं के विद्यमान होने से यहां पर बड़े एयरपोर्ट की नितांत आवश्यकता है। कोटा

में आर्थिक सम्पन्नता बढ़ने से यहां पर प्रतिदिन की फ्लाईट के लिए अच्छी मात्रा में ग्राहक मिलने की पूर्ण संभावना है। कोटा की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए पूरे देश से कन्टेक्टीविटी होना जरूरी है इसीलिए सरकार को यहां नये एयरपोर्ट को स्थापित करने की योजना बनानी चाहिए। **–नफा नुकसान टीम**

संकलन : पुनीत जैन (99291 06227), धैर्यवर्द्धन सिंह (99281 20134)

कोटा को चाहिए नया औद्योगिक क्षेत्र

कोटा शिक्षानगरी के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में कोचिंग कारोबार से ही कोटा की अर्थव्यवस्था को ताकत मिल रही है। कोटा में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की अच्छी संभावना है लेकिन औद्योगिक भूमि की कमी के कारण आशातीत गति से औद्योगिक गतिविधियां नहीं पनप पा रही हैं। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार कोटा में नये औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। कोटा में स्टोन पार्क स्थापित करने की काफी संभावना है लेकिन सरकार के स्तर पर कई घोषणाएं होने के बावजूद आज तक कोटा में स्टोन पार्क विकसित नहीं हो सका है। एसएसआई अध्यक्ष सुरेश बंसल के अनुसार कोटा के चारों तरफ वन भूमि होने से यहां नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने में परेशानी आ रही है क्योंकि वन भूमि को औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग लेने हेतु केन्द्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। कुबेर औद्योगिक क्षेत्र के पास और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की योजना है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई है। रानपुर के आगे इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए करीब 300 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। कारोबारियों के अनुसार रोड नं. 7 के पीछे खाली जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। **– ननुटी**

संभावनाओं वाला कुबेर औद्योगिक क्षेत्र कई समस्याओं से है त्रस्त

कोटा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर रानपुर स्थित कुबेर औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारी कई समस्याओं से त्रस्त हैं। इन समस्याओं में शहरी परिवहन की कमी, कामगारों की कमी, कमजोर जलापूर्ति, सामान्य सुविधाओं का अभाव, सुरक्षा की समस्या, स्थानीय ट्रांसपोर्ट का अभाव, कर छूट का प्रावधान ना होना, अनियमित विद्युत आपूर्ति, रॉ मैटेरियल ना मिलना, इंटरनेट, डाक व कोरियर सेवाओं का कमजोर प्रदर्शन इत्यादि प्रमुख हैं। अगर इन समस्याओं का हल किया जाये तो कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। गौरतलब है कि कुबेर औद्योगिक क्षेत्र तीन जोनों फूड पार्क जोन, एजुकेशन जोन और इण्डस्ट्री जोन में विभाजित है लेकिन सुविधाओं के अभाव में मात्र 30 से 40 औद्योगिक इकाइयों में ही औद्योगिक गतिविधियां हो रही हैं।

अपर्याप्त है शहरी परिवहन की सुविधा

कुबेर औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख औद्योगिक इकाई ट्रिम इंजीनियरिंग के निदेशक राजकुमार जैन ने बताया कि कोटा शहर से कुबेर औद्योगिक क्षेत्र के लिए परिवहन की सुविधा अपर्याप्त है। कोटा शहर से कुछ टेम्पो और केवल दो सरकारी बसों द्वारा परिवहन किया जा सकता है। इससे कोटा शहर से आने वाले ग्राहकों और कामगारों को कुबेर औद्योगिक क्षेत्र आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवहन सुविधा का अभाव होने के कारण यहां कामगार आने में आनाकानी करते हैं। कामगारों , ग्राहकों और कंपनी अधिकारियों को लाने-छोड़ने के लिए कार्यरत इकाइयों को व्यक्तिगत स्तर पर अपने वाहनों द्वारा परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है।

कामगारों की कमी

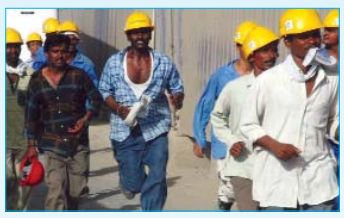

कोटा शहर से दूरी व परिवहन की कमी जैसी विभिन्न समस्याओं के चलते कामगार कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। जैन के मुताबिक उक्त कारणों से कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों का अभाव रहता है और अत्यधिक मजदूरी पर कामगार रखने पड़ते हैं। सरकार यहां मजदूरों के आवास व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाए तो यहां की औद्योगिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक होगा।

कमजोर जलापूर्ति

अन्नत एनरसोल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रजनीश एस. चौहान ने बताया कि कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में जलापूर्ति कमजोर है। लोगों को अपने स्तर पर पानी के बोरवेल करवा कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहीं पहाड़ी इलाका होने के कारण बोरवेल खुदवाने में समस्या आती है।

सामान्य सुविधाओं का अभाव

किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में सुचारू तरीके से कार्य संचालन के लिए शॉपिंग सेन्टर होना आवश्यक होता है, जहां कारोबारियों को कारोबार से संबंधित चीजें आसानी से मिल सकती हों लेकिन कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में शॉपिंग सेन्टर का अभाव है। रीको अगर यहां शॉपिंग सेन्टर विकसित करे तो कारोबारियों को फोटोस्टेट, रेस्टोरेंट, रॉ-मैटेरियल और अन्य आवश्यक सामानों जैसी आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल जाएगी। जैन के अनुसार कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं नहीं होने से यहां से करीब 8 किलोमीटर दूर अंतरपुरा के बाजार जाना पड़ता है।

स्थानीय ट्रांसपोर्ट का अभाव

कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में लोडिंग टेम्पो, ट्रक और अन्य स्थानीय ट्रांसपोर्ट का अभाव भी यहां की औद्योगिक गतिविधियों के लिए नकारात्मक साबित हो रहा है। जैन के मुताबिक स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट

की सुविधा मुहैया नहीं होने से अंतरपुरा से ट्रांसपोर्ट के साधन मंगवाने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि मण्डाना स्थित सूखा बंदरगाह के लिए गाड़ी भेजना भी महंगा पड़ता है।

अनियमित विद्युत आपूर्ति

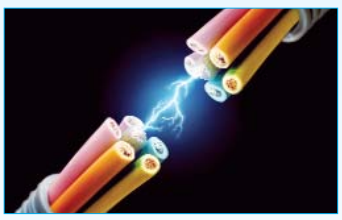

कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक बार लाईट ट्रिपिंग होती है। इससे औद्योगिक इकाइयों को काफी नुकसान होता है। चौहान ने बताया कि उनका एलईडी लाईट निर्माण कार्य है और इसके लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है लेकिन दिन में 8 से 10 बार ट्रिपिंग होने से औद्योगिक निर्माण कार्य में व्यवधान आता रहता है। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग को इस समस्या से बार-बार अवगत कराया गया है लेकिन विभाग की ओर से ग्रिड से आपूर्ति में दिक्कतों को हवाला दिया जाता है। कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान अतिआवश्यक है।

कर छूट का प्रावधान ना होना

जैन के मुताबिक शहर से बहुत दूर और नये औद्योगिक क्षेत्र में कारोबारियों को बेहद कठिन परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है लेकिन फिर कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में कारोबारियों को किसी भी प्रकार की करों में छूट नहीं मिली हुई है। अगर सरकार नये कुबेर औद्योगिक क्षेत्र जैसे नये औद्योगिक क्षेत्रों में कर छूट का प्रावधान देती है तो प्रदेश के कारोबार में अधिक इजाफा हो सकता है।

रॉ-मैटेरियल का न मिलना

जैन ने बताया कि राजस्थान में औद्योगिक गतिविधियों में कमी का कारण यहां किसी भी प्रकार का रॉ मैटेरियल ना मिलना है। सभी प्रकार के रॉ मैटेरियल गुजरात, महाराष्ट्र और नई दिल्ली इत्यादि जगहों से मंगवाने पड़ते हैं। राजस्थान को औद्योगिक स्तर पर प्रगति करनी है तो यहां पर रॉ-मैटेरियल निर्माण करने वाले उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। सरकार को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

- नफा नुकसान टीम

कुबेर औद्योगिक क्षेत्र के पास डेयरी फार्म खोलने की वृहद् संभावना

कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में शिव एडिबल ऑयल और दिव्या फूड जैसी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को अत्यधिक मात्रा में दूध की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन इन औद्योगिक इकाइयों में मांग के मुकाबले आपूर्ति में काफी कमी दर्ज की जा रही है इसीलिए कुबेर औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक डेयरी फार्म स्थापित करने की वृहद् कारोबारी संभावना उजागर हो रही हैं। डेयरी फार्म 1000 से 5000 मीटर की भूमि में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। अच्छी किस्म के दुधारू पशु और देखभाल करने के लिए ग्रामीण डेयरी फार्म कारोबार के लिए मूलभूत आवश्यकता है। कोटा स्थित कुबेर औद्योगिक क्षेत्र के पास ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से डेयरी फार्म कारोबार स्थापित करने की अच्छी संभावना है। यह कारोबार अन्य कारोबार से अपेक्षाकृत कम पूंजी पर शुरू किया जा सकता है। जानकारों के अनुसार कोटा में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध की खपत होती है इसीलिए कोटा में डेयरी कारोबार में अच्छी संभावना है। कुबेर औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित

इलाकों में डेयरी फार्म स्थापित करना आकर्षक इसीलिए हो गया है क्योंकि यहां स्थित दो प्रमुख डेयरियों शिव ऑयल और दिव्या फूड में उत्पादित सारा दूध खप जायेगा। इन डेयरियों में फैट के आधार पर दूध की कीमत तय की जाती है। डेयरी फार्म कारोबार में एक जमीन और दुधारू पशुओं पर निवेश करना होता है फिर केयर टेकर और नियमित टीकों पर निवेश करना होता है। इसके बाद निरंतर अच्छी कमाई होती रहती है क्योंकि वर्तमान में दूध की मांग आपूर्ति से अधिक बनी हुई है। इसके अलावा दुग्ध उत्पाद जैसे छाछ, दही और घी से भी अच्छी कमाई हो सकती है।

- नफा नुकसान टीम

ढल रहा है कोटा स्टोन कारोबार

कोटा का स्टोन अपनी स्थायी प्रकृति और लंबे समय तक चलने के कारण विश्वप्रसिद्ध है लेकिन गत कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं में कोटा स्टोन की मांग घटने से कोटा स्टोन के कारोबार में कमी दर्ज की गई है। इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में कोटा स्टोन का कारोबार करने वाली करीब 10 से 15 इकाइयां बंद होकर बिक गई हैं। हालांकि कोटा स्टोन कारोबारियों को विश्वास है कि देश में नई सरकार आने से इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में सुधार आने के कारण दो से तीन साल में कोटा स्टोन के कारोबार में सुधार आ सकता है।

समय के साथ बदलाव: अन्य स्टोन के साथ कोटा स्टोन की मांग सिरेमिक टाईल्स से प्रभावित हुई है। कोटा स्टोन के कारोबारियों ने इस समस्या से निपटने के लिए अब टाईल्स भी निर्मित करनी शुरू कर दी हैं। रफ मॉल में रिवर पॉलिस के माध्यम से कोटा स्टोन को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। हाड़ोती कोटा स्टोन इण्डस्ट्री एसोसिएशन के महासचिव जम्बु कुमार जैन ने बताया कि कोटा स्टोन से अहमदाबाद में काफी आकर्षक स्टोन वर्क किया गया है। हाल ही में कोटा स्टोन का एक प्रमुख शॉपिंग मॉल कांकरिया शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल किया गया है।

कोटा स्टोन कोटा का प्रमुख कारोबार: जैन ने बताया कि कोटा संभाग में प्रतिवर्ष 40 करोड़ वर्गफीट कोटा स्टोन का उत्पादन होता है। इस कारोबार से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। कोटा में कोटा स्टोन का प्रतिवर्ष करीब 500 से 600 करोड़ रुपये का कारोबार होता है।

लाईम और सेण्ड स्टोन निर्यात में संभावनाएं : कोटा स्टोन कारोबारियों के अनुसार कोटा स्टोन कारोबार के अलावा कोटा में सेण्ड स्टोन और लाईम स्टोन प्रोसेसिंग और निर्यात कारोबर में अच्छी संभावना उजागर हो रही हैं। कोटा के आसपास के क्षेत्रों में सेण्डस्टोन माईन्स एरिया कच्चे माल की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहा है। कोटा में मण्डाना स्थित सूखा बंदरगाह भी निर्यात के लिए अच्छी संभावनाएं मुहैया करवा रहा है।

- नफा नुकसान टीम

इंजीनियरिंग कोचिंग और शिक्षा का सेचुरेशन

पांच वर्षों की औद्योगिक मंदी और मांग की अपेक्षा अत्यधिक आपूर्ति के कारण इंजीनियरिंग कोचिंग और शिक्षा में ऊपरी सीमा (सेचुरेशन) आने के संकेत मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग और शिक्षा के लिए कोटा शहर देशभर में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र के कारोबारियों से बातचीत करने पर इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने करने वाले छात्रों के रुझान में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं।

गुरुकुल इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक राकेश गौतम के अनुसार इंजीनियरिंग के प्रति छात्रों का रुझान कम हो रहा है। वर्ष 2008 तक इंजीनियरिंग के प्रति छात्रों का मोह उच्चतम स्तर पर था लेकिन फिर आर्थिक मंदी के कारण इसमें गिरावट आयी। 2010 से 2012 तक इस रुझान में सुधार दर्ज किया गया लेकिन इंजीनियरिंग के प्रति आकर्षण में फिर से कमी दर्ज की जा रही है। अपेक्स इंजीनियरिंग के कन्वीनर महेश गौतम के अनुसार वर्ष 2008 के मुकाबले वर्तमान में कई इंजीनियरिंग संस्थान खुल गये हैं और सीटें भी काफी बढ़ गयी हैं।

सीटें नहीं भरने से ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग के प्रति छात्रों का आकर्षण घट रहा है लेकिन वर्ष 2008 के मुकाबले वर्तमान में इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की संख्या को देखा जाये तो इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की संख्या में 20 प्रतिशत इजाफा नजर आयेगा।

क्रिएटिविटी पर निर्भर होगी सफलता

वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्द्धा है। आशातीत सफलता अर्जित करने के लिए हर किसी को अपना सर्वोत्तम परिणाम देना होता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों को सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक कार्यों पर निर्भर होना होगा। गुरुकुल इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक राकेश गौतम के अनुसार जैसे इंजीनियरिंग में सेचुरेशन आ रहा है, वैसे-वैसे अच्छा परिणाम देने वाले संस्थानों की पूछ बढ़ेगी।

गौतम ने कहा कि उनकी संस्था में छात्रों को औद्योगिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य को समझाने के लिए सुसज्जित कार्यशाल स्थापित की गई है। वहां छात्रों ने कई प्रकार के रचनात्मक प्रयोग कर इंजीनियरिंग उत्पाद बनाए हैं। इनमें साइकिल से खेतों में पानी सींचने वाली मशीन, कई काम करने वाली आटा मशीनें इत्यादि प्रमुख हैं। इन रचनात्मक कार्यों से ही इंजीनियरिंग छात्रों को औद्योगिक क्षेत्र की समझ आती है और एक इंजीनियरिंग संस्थान सही मायनों में एक सक्षम इंजीनियर तैयार कर पाता है। अपेक्स इंजीनियरिंग के महेश गौतम ने बताया कि कोटा में काफी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गये हैं लेकिन अच्छी शिक्षा और रचनात्मक कार्य कराने वाले संस्थान ही अच्छा परिणाम देने में सक्षम हो पाते हैं। उनका संस्थान अपने कुल खर्च का 25 प्रतिशत इनोवेशन पर खर्च करता है।

– नफा नुकसान टीम

खाद्यान्न को बचाना है तो वेयरहाउसिंग कारोबार को देना होगा प्रोत्साहन

वेयरहाउसिंग कारोबारियों को वेयरहाउस को लीज पर देने में सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स से पूर्णत: छूट मिले तो कोटा समेत सारे राज्य में वेयरहाउसिंग कारोबार पनप सकता है। कोटा के वेयरहाउसिंग कारोबारी नेमीचन्द चन्द्र प्रकाश प्रा. लिमिटेड के निर्मल कुमार जैन ने बताया कि हिन्दुस्तान में कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण ही प्रतिवर्ष लाखों टन खाद्यान्न खराब हो जाता है। इसीलिए सरकार को वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने बताया कि वेयरहाउसिंग कारोबार पर किसी प्रकार का सर्विस टैक्स नहीं है लेकिन यदि कोई कारोबारी वेयरहाउस को किसी अन्य व्यापारी को भण्डारण के लिए लीज पर देता है तो उसे 12.5 प्रतिशत की दर से सर्विस टैक्स चुकाना होता है। इस प्रकार नये कारोबारी के लिए वेयरहाउसिंग कारोबार अनाकर्षक हो गया है। इसके अलावा वेयरहाउसिंग कारोबार की ज्यादातर कमाई इनकम टैक्स में खप जाती है।

उनके अनुसार वेयरहाउसिंग पर मिलने वाली सब्सिडी भी समय पर नहीं आती है। नाबार्ड के फंड से वर्ष 2006-07 की सब्सिडी अभी तक नहीं मिल पायी है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वेयरहाउसिंग फर्म रुकमणी देवी गर्ग एग्रो इम्पेक्स प्रा. लि. के विशाल गर्ग ने बताया कि बजट में वेयरहाउसिंग कारोबार के संबंध में की गई घोषणाएं स्पष्ट नहीं हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है।

संभावनायुक्त लेकिन लागत से बाहर

जैन के अनुसार वर्तमान में कोटा संभाग में शामिल कोटा, बारां, बूंदी और रामगंज मंडी में 40 लाख बोरी भण्डारण की क्षमता है लेकिन वर्तमान उपज के अनुसार कोटा संभाग में अभी भी 40 लाख बोरी भण्डारण के वेयरहाउस की आवश्यकता है परंतु करोड़ों रुपये निवेश करने के बाद भी इस कारोबार में रिटर्न नहीं है। उनके अनुसार वेयरहाउस निर्माण करने की लागत करीब 600 रुपये प्रति वर्ग फीट है और जमीन की कीमतें आवश्यक जगहों पर करीब 400 रुपये प्रति वर्ग फीट हैं लेकिन वेयर हाउस का किराया 5 से 6 रुपये प्रति वर्ग फीट ही चल रहा है यानि एक करोड़ रुपये के निवेश पर 60000 रुपये का लाभ। उसमें से भी सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स से लाभ राशि कम हो जाती है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि में रूपान्तरण करवाने की लागत को दोगुना कर दिया गया है। इससे भी वेयरहाउस स्थापित करना अनाकर्षक हो गया है। अगर वेयरहाउस के निर्माण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाये तो वेयरहाउसिंग कारोबार पनप सकता है। कोटा संभाग खाद्यान्न उत्पादन के लिहाज से कोटा का प्रमुख शहर है। ऐसे में यहां वेयरहाउस कारोबार के लिए व्यापक कारोबारी अवसर हैं।

– नफा नुकसान टीम

Manufacturer of

All types of CNC Turned Precision Components
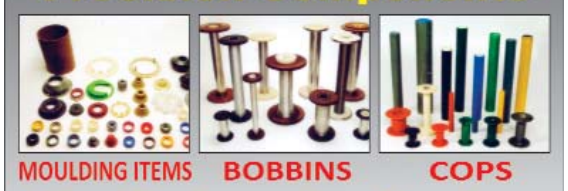
MOULDING ITEMS BOBBINS COPS
Trim Engineering Services
Office Add.: 7-Aerodrome Circle, Kota-324005 (Rajasthan),India
Factory Add.: H-222 Kuber Industrial Area, Ranpur, Kota (Raj.)
Contact no.: +91-744-2845055 & 2845044, M. +91-9352602343
Email: info@trimengineering.in, trim_triman@yahoo.co.in
Web: www.trimengineering.in

With Best Complements from
NC
Nemi Chand Chandra Prakash Pvt. Ltd.
(Moikalan wale)
Ware Housing
Nami Chand / Chandra Prakash
Grain Marchant & Commosion Agent
N.C. & Co.
Dhania Grading Unit
Deals in all type of Agri Commodities
TRADING FINANCING WAREHOUSING
Office : B-100, Seth Bhamashah
Krishi Upaj Mandi, Kota-324005 (Raj.)
Head Office : Plot No. A, 211(B), I.P.I.A.,
Road No. 6, Anantpura, Kota (Raj.)
Chandra Prakash Jain 94141 88044
Nirmal Kumar Jain 98290 36044

With Best Compliment From
B K BIRLA GROUP OF COMPANIES
मंगलम
For Quality Strength and Durability
Always insist on
BIRLA UTTAM BRAND
ORDINARY PORTLAND & PORTLAND POZOLANA CEMENT
OF
Mangalam cement Ltd.
सर्व श्रेष्ठ – सर्वोत्तम
बिरला उत्तम
Regd. Office
Aditya Nagar - 326520
Morak Distta. Kota (Rajasthan)
Phone : (07459) 232156
Fax : (07459) 232036, 232156
E-mail : mclmorak@kappa.net.in
www.mangalamcement.com
Kota Office
93, Dashera Scheme
P.O. Dadabari 324009
Kota (Rajasthan)
Phone : (0744) 2500266, 3098600
Fax : (0744) 2500178
E-mail : mclkta@kappa.net.in

With Best Complements From
Devendra Stone & Marbel
A Unit of Devendra Dall Mill's
G-398, I.P.I.A, Kota
Devendra Kumar & Company
Grain Merchant & Commission Agent
A16, Bhamasha Mandi, kota
Devendra Kumar Jain 98290-36783
Jambu Jain 9352990623
Paras Kumar Jain 9460054485
Jitendra Kumar Jain 9414189438

With Best Complements from
SSI THE SSI ASSOCIATION, KOTA
Ogranisation of Small Scal Industries of Hadoti Region: Affiliated at All India Level

Suresh Bansal
(President)
Mob: 9829046655

Navendu Dwivedi
(Secretary)
Mob: 9829037941
"PURUSHARTH BHAWAN", Road No. 5, Indraprastha
Industrial Area, Kota - 324 005. Tel: 0744-2424164,
Fax : 0744-2428748, E-mail : ssiakota@gmail.com

कोटा अर्थव्यवस्था के स्तम्भ बन गए हैं हॉस्टल

कोटा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में यहां मौजूद छोटे- बड़े करीब 500 हॉस्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोटा की अर्थव्यवस्था में हॉस्टलों से 20 से 25 करोड़ रुपये की नकदी का प्रवाह होता है। गौरतलब है कि कोटा इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की ट्यूशन के लिए देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान के रूप में स्थापित हो गया है। कोटा शहर में करीब 1.50 लाख बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन छात्रों में ज्यादातर देश के अन्य भागों के रहने वाले हैं और इसीलिए उनको रहने के लिए हॉस्टल की आवश्यकता पड़ती है। एक बच्चे के हॉस्टल में ठहरने का खर्चा प्रतिमाह करीब 5 से 10 हजार रुपये आता है।

रीको भूमि पर हॉस्टल निर्माण से उपजा विवाद

रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित चार बड़ी कोचिंग सेन्टरों के समीप इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर मांग के अनुरूप कारोबारियों ने कोचिंग स्थापित कर लिये। रीको ने कारोबारियों को नोटिस भेज कर सेटबैक नियमों के अनुसार निर्माण नहीं करने और प्रति वर्ग मीटर 9000 रुपये जमा कराने के नोटिस भेजे हैं। व्यापारियों का कहना है कि चार बड़े कोचिंग सेन्टरों को औद्योगिक क्षेत्र में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी लेकिन हॉस्टल निर्माताओं को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में करीब 40 से 45 हॉस्टल निर्मित हो गये हैं और इनके निर्माण पर कारोबारियों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया है।

लाखों बच्चो रहते हैं हॉस्टलों में

गौरतलब है कि कोटा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कोचिंग है। पूरे देशभर से करीब 1.50 लाख बच्चे कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोटा में करीब 1.25 लाख बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। कोटा एक शैक्षणिक नगरी है और इसका अस्तित्व बनाये रखने के लिए हॉस्टल का अस्तित्व भी बनाये रखना आवश्यक है। एसएसआई के अध्यक्ष सुरेश बंसल के अनुसार सरकार को इस समस्या का तुरंत सकारात्मक हल निकालने पर पहल करनी चाहिए। एसएसआई के पूर्व अध्यक्ष अनिल मूंदडा के अनुसार हॉस्टल को स्थायी करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।

होटल और हॉस्टल के अर्थान्वयन में दिक्कतें

रीको के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में होटल स्थापित करना एक व्यावसायिक गतिविधि है जबकि मूंदडा के अनुसार एमएसएमई अधिनियम में होटल को औद्योगिक गतिविधियों की सूची में शामिल किया गया है इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड मालिक कानूनन होटल और हॉस्टल निर्मित कर सकता है। जहां तक होटल और हॉस्टल के नाम की बात है, शाब्दिक अर्थ और कार्यप्रणाली के हिसाब से होटल और हॉस्टल दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों जगहों को राशि देकर सराय की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

हजारों लोगों को मिल रहा है रोजगार

कोटा में 1.25 लाख बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। इन बच्चों को हॉस्टल की सुविधा प्रदान करने से करीब 7 से 8 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। यातायात, टिफिन सेन्टर और अन्य सुविधाएं देने से लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं इससे कोटा शहर की अर्थव्यवस्था में प्रतिमाह 20 से 25 करोड़ रुपये का प्रवाह भी होता है।

– नफा नुकसान टीम

नई पीढ़ी के अनुसार ज्वैलरी का निर्माण कर रहे हैं ज्वैलर्स

ज्वैलर्स अपने ग्राहकों के लिए परंपरागत ज्वैलरी के अलावा अब नयी पीढ़ी की पसंद के अनुसार भी ज्वैलरी निर्माण करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। युवाओं में डायमण्ड और प्लेटिनम ज्वैलरी का क्रेज ज्यादा बढ़ रहा है। कोटा की प्रमुख ज्वैलरी फर्म वल्लभम् सर्राफ के संस्थापक श्रीनाथ सर्राफ ने कहा कि उनकी फर्म मुख्य रूप से परंपरागत राजस्थानी ज्वैलरी का निर्माण करती है लेकिन उन्होंने नई पीढ़ी की पसंद अनुसार भी ज्वैलरी का निर्माण करना शुरू किया है इसीलिए उनके यहां यूथ को पसंद आने वाली लाईट और फैंसी ज्वैलरी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। उनकी फर्म की खासियत कुन्दन,मीना और जड़ाऊ के आभूषण निर्माण करने में है। सर्राफ ने बताया कि ज्वैलरी कारोबार विश्वास पर आधारित कारोबार है इसीलिए उनकी फर्म में ग्राहकों के विश्वास को कायम रखने के उपाय किए जाते हैं। ग्राहकों को अच्छी ज्वैलरी प्रदान करने के लिए अनुभवी ज्वैलरी कारीगरों की सेवा मिलना भी काफी अहम होता है। अनुभव से बनाई गई ज्वैलरी देखने वालों का मन मोह लेती है। सर्राफ ने बताया कि वर्तमान में एमसीएक्स और वायदा कारोबार से ज्वैलरी कारोबारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर पल सोना, चांदी की कीमतों में आने वाले उतार–चढ़ाव का ध्यान रखना पड़ रहा है। सरकार द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी भी 10 प्रतिशत करने से सोने से आभूषण निर्माण की लागत बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की स्वर्ण नीति आभूषण कारोबार के लिए सही नहीं है। सरकार द्वारा अनावश्यक अंकुश लगाने से व्यापार प्रभावित होता है। उनके मुताबिक बजट में रंगीन रत्नों को शुल्क मुक्त करने से राजस्थान का रत्न उद्योग और अधिक विकसित होगा।

– नफा नुकसान टीम